(ग) गुवा में अपेक्षित टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण गुना-बीना खण्ड पर अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से अभी व्यावहारिक नहीं है ।

खण्डवा-मऊ—इन्दौर और खण्डवा/अजमेर पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने का न तो यातायात की दृष्टि से औचित्य है और न मार्ग में पर्याप्त लाइन क्षमता के अभाव के कारण वैसा करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक ही है ।

अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

1183. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने अधिनियमों का हिन्दी में प्राधिकृत अनुवाद कराया गया है ; और

(ख) कितने अधिनियमों का अन्य भाषाओं में अनुवाद कराया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1972 की अवधि के दौरान, 115 केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं । उक्त अवधि के दौरान, 127 केन्द्रीय अधिनियमों का अन्य भाषाओं में (4 का आसामी में, 16 का गुजराती में, 8 का मराठी में, 56 का उड़िया में तथा 43 का उर्दू में अनुवाद किया जा चुका है ।

Imposition of Condition for Taking Up Rail Projects in States

1184. SHRI E. V. VIKHE PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have imposed any condition precedent to the taking up of new Rail projects into States from which requests are received for the purpose;

(b) if so, the nature of such condition; and

(c) whether any of the States have so far complied with the condition and, if so, the names thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). For construction of new rail lines required for the development purposes, a new approach is under consideration on the following basis, will be seen from para 41 of the speech of the Minister of Railways while presenting the Budget for 1973-74 on 20th February, 1973.

(i) Exemption, full or partial, from payment of dividend liability to the General Revenues during the period of construction and for a specified number of years after completion and opening to traffic;

(ii) Participation of State Governments or local authorities, in reducing the cost of construction by giving the land and labour content of construction free of cost;

(iii) Suitable adjustment upwards of fares and freight structure applicable to the newly constructed line which in common parlance is called 'inflation of chargeable mileage'; and

(iv) Levy of fares and freight on a discontinuous basis so as to be a